(2008) 2 एस.सी.आर. 724

हरप्रसाद और अन्य

बनाम

रनवीर सिंह और अन्य

(2008 की आपराधिक अपील संख्या 294)

12 फरवरी, 2008

(डाॅ अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे.जे.)

1- आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, धारा 173 -190 विरोध याचिका के साथ झूठा शपथ-पत्र दायर सत्र न्यायाधीश ने माना कि, इसके कारण मजिस्ट्रेट कोई आदेश पारित नहीं कर सकता था - उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया - मजिस्ट्रेट के आदेश की सत्यता को माना गया क्योंकि मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश सीआरपीसी की धारा 173 के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करते हुए दिया गया था और विरोध याचिका से संबंधित नहीं था।

आपराधिक पुनरीक्षण में सत्र न्यायाधीश ने माना कि चूंकि विरोध याचिका के साथ एक झूठा हलफनामा दायर किया गया था, इसलिए मजिस्ट्रेट मामले में आगे नहीं बढ़ सकते थे और आदेश पारित नहीं कर सकते थे। उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायाधीश के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश विरोध याचिका पर पारित नहीं किया गया था बल्कि सीआरपीसी की धारा 173 के

संदर्भ में प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करते हुए पारित किया गया था, इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

अदालत ने अपील खारिज करते हुए कहाः-

तथ्यात्मक स्थिति यह दर्शाती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश पुलिस रिपोर्ट पर विचार करते हुए दिया गया था और विरोध याचिका से संबंधित नहीं था, इसलिए उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण किसी भी प्रकार की दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। (पैरा० 8)(729 बी सी)

अभिनंदन झा और अन्य बनाम दिनेश मिश्रा (एफआईआर) 1968 एसपी 117) का हवाला दिया गया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 294/2008

2001 की आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 147 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 24.11.2006 से।

अपीलकर्ताओं की ओर से शकील अहमत सैयद, शैल कुमार द्विवेदी, एएजी।

उत्तरदाताओं के लिए देबाशीष मिश्रा, अणुव्रत शर्मा, एस एन पांडे, वंदना मिश्रा और विभा द्विवेदी।

न्यायालय का निर्णय डाॅ. अरिजीत पसायत जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में चुनौती इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को दी गई है जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा दायर पुनरीक्षण की अनुमति दी गई है। 2000 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 272 में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, 13, अलीगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-11-2000 की वैधता पर सवाल उठाते हुए पुनरीक्षण दायर किया गया था। जिसमें इस तर्क को स्वीकार किया गया था कि मामले के मुखबीर ने विरोध याचिका के साथ एक गलत हलफनामा दायर दिया था और इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी।

3. विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष यह रूख अपनाया गया कि जब तक विरोध याचिका दायर की गई तब तक सूचना देने वाले की मृत्यु हो चुकी थी और अंगूठे के निशान के साथ झूठा हलफनामा तैयार किया गया था। चूंकि सूचक की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी इसलिए मामले में विद्वान मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। इसे विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा स्वीकृति मिल गई। उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश में माना था कि आदेश विरोध याचिका पर पारित नहीं किया गया था और वास्तव में आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (सक्षेप में सी- आर- पी- सी-) की धारा 173 के संदर्भ में प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने पर पारित किया गया था।

4. अपील कर्ताओ के विद्वान वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय ने यह मानकर गंभीर गलती की है कि विरोध योचिका के साथ गलत हलफनामा दाखिल करना, यदि कोई हो तो, महत्वहीन है। उनके अनुसार, जब विद्वान मजिस्ट्रेट ने विरोध याचिका पर कार्रवाई की, तो यह दृष्टिकोण कायम नहीं रखा जा सकता कि विरोध याचिका के साथ

हलफनामा का कोई परिणाम नहीं था।

5. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के वकील ने कहा कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को पढ़ने से पता चलता है कि आदेश का आधारा विरोध याचिका पर नहीं था, बल्कि सी. आर. पी. सी. की धारा 173 के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट से संबंधित था।

6. एक मात्र प्रश्न जो विचारणीय है वह यह है कि क्या आदेश विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा विरोध याचिका पर पारित किया गया या पुलिस रिपोर्ट पर।

7. अभिनंदन झा और अन्य बनाम दिनेश मिश्रा (ए.आई.आर 1968 एससी 117) मामले में इस अदालत के फैसले का संदर्भ लिया जा सकता है, जहां इसे इस प्रकार रखा गया थाः

8. अब केवल पूछताछ और परीक्षणों में आपराधिक अदालतों के क्षेत्राधिकार से संबंधित अध्याय 14 में आने वाली धारा 190 का उल्लेख करना आवश्यक है। वह अनुभाग ‘‘कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक शर्ते’’ शीर्षक के अन्तर्गत पाया जाना है, और उपधारा (1) इस प्रकार हैः

"(1) इसके बाद प्रदान किए गए को छोड़कर, कोई भी प्रेसिडेसी मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट या उप विभागीय मजिस्ट्रेट और इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त कोई अन्य मजिस्ट्रेट, किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता हैः-

(ए) उन तथ्यों की शिकायत प्राप्त होने पर ऐसे अपराध का गठन करते है;

(बी) किसी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे तथ्यों की लिखित रिपोर्ट पर;

(सी) पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त जानकारी पर, या अपने स्वयं के ज्ञान या संदेह पर, कि ऐसा अपराध किया गया है।''

9. अध्याय 14 में आने वाले पूर्वगामी अनुभागों से, यह देखा जाएगा कि यह सुनिश्चित करने के लिए जो विस्तृत प्रावधान किए गए हैं कि रिपोर्ट किए गए अपराध की जांच हो और जांच कानून की सीमा के भीतर की जाए, अभियुक्त् को बिना किसी उत्पीड़न के और बिना किसी अनावश्यक या अनावश्यक देरी के पूरा भी कर दिया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जांच करने का तरीका और तरीका पूरी तरह पुलिस पर छोड़ दिया गया है और मजिस्ट्रेट के पास, जहां तक हम देख सकते हैं, इनमें से किसी भी प्रावधान के तहत इसमें हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है। अगर जांच करने पर, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या जांच करने वाले अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजने काे ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार नहीं है, तो धारा 169 कहती है कि अधिकारी अभियुक्त को, यदि हिरासत में है, मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने के लिए मुचलका भरने पर रिहा कर देगा। इसी प्रकार, दूसरी ओर, यदि अध्याय 14 के तहत पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या जांच करने वाले अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी आरोपी को मजिस्ट्रेट के पास भेजने काे उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत या उचित आधार है तो मजिस्ट्रेट के लिए, ऐसे अधिकारी को, धारा 170 के तहत, अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजने या, यदि अपराध जमानत है तो ऐसे

मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी उपस्थिति के लिए सुरक्षा लेने की आवश्यकता होती है लेकिन, चाहे कोई मामला धारा 169 के तहत आता हो, या धारा 170 के तहत, जांच पूरी होने पर, पुलिस अधिकारी को धारा 173 के तहत उसमें बताए गए तरीके से, मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें विभिन्न विवेचन शामिल हो। यह सवाल कि क्या मजिस्ट्रेट को धारा 173 के तहत रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुलिस का आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश देने की शक्ति मिली है, वास्तव में रिपोर्ट प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग किए जाने वाले क्षेत्राधिकार की प्रकृति पर निर्भर करता है।

10. हालांकि ऐसा हो सकता है कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक रूप से निपटाया जा सकता है और हालांकि मजिस्ट्रेट के पास कुछ पर्यवेक्षी शक्तियां हो सकती है, फिर भी हम इस विचार से सहमत नहीं है कि केवल इन विचारों से यह कहा जा सकता है कि जब पुलिस रिपोट प्रस्तुत करती है कि अभियुक्त को मुकदमें के लिए भेजने का कोई मामला नहीं बनता है, मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को आरोप.पत्र दाखिल करने का निर्देश देने का अधिकार है। लेकिन, हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि मजिस्ट्रेट बिल्कुल शक्तिहीन है, क्योंकि जैसा कि बाद में संकेत दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट के पास किसी अपराध का संज्ञान लेने और कानून के अनुसार आगे बढ़ने का अधिकार है। हमें धारा 173(3)के तहत ऐसी कोई शक्ति नहीं मिलती, जैसा कि ऊपर उद्धत कुछ निर्णय में अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि हमने विभिन्न निष्कर्षों पर पहुंचने के विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाए गए, दृष्टिकोण का व्यापक रूप से संकेत दिया है, हम उन

निर्णयों को विस्तार से संदर्भित करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

यह देखा जाएगा कि कोड ''चार्जशीट'' या ''अंतिम रिपोर्ट'' जैसे अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करता है, लेकिन नियमों और विनियमों वाले पुलिस मैनुअल में यह समझा जाता है कि पुलिस द्वारा संहिता की धारा 170 के तहत दायर की गई एक रिपोर्ट को ''चार्जशीट'' कहा जाता है। लेकिन धारा 169 के तहत भेजी गई रिपोर्ट के संबंध में, यानी जब अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं होते हैं, तो इसे अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरह से ''संदर्भित आरोप'', ''अंतिम रिपोर्ट'' या ''सारांश'' कहा जाता है।

हमें इस मामले में उठने वाले प्रश्न पर ऊपर बताई गई, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचार करना होगा। हम पहले ही अध्याय 14 की योजना का उल्लेख कर चुके हैं, साथ ही रिशबुद और इन्दरसिंह मामले (एफआईआर 1955 एस.सी. 196) में इस अदालत की टिप्पणियों का उल्लेख कर चुके हैं कि आरोपी को सजा देने का कोई मामला है या नहीं, इस बारे मेंे राय की जानकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा चलाने पर मामला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी पर छोड़ दिया जाता है। जहां तक हम देख सकते हैं कि ऐसा कोई स्पष्ट शक्ति नहीं है, जो हमले के तहत प्रकृति का आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र देती हो; न ही ऐसी कोई शक्ति निहित की जा सकती है। यदि मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा बनाई गई राय से सहमत नहीं है, तो रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए मजिस्ट्रेट पर निश्चित रूप से कोई दायित्व नहीं है। उन परिस्थितियों में, यदि उसे अभी भी संदेह है कि कोई अपराध किया गया है, तो वह

पुलिस की राय के बावजूद, संहिता की धारा 190(1) (सी) के तहत संज्ञान लेने का हकदार है। वह प्रावधान, हमारी राय में स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए है कि अपराध बक्शे नहीं जा सके, और न्याय तब भी लागू किया जा सके, जहां व्यक्तिगत रूप से पीड़ित व्यक्ति मुकदमा चलाने के लिए अनिच्छुक या असमर्थ है, या पुलिस, या तो लापरवाही से या वास्तविक त्रुटि के कारण, अपराध का गठन करने वाले तथ्यों को स्थापित करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहती है, इसलिए किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट को एक बहुत व्यापक शक्ति प्रदान की जाती है, न केवल जब उसे किसी तीसरे व्यक्ति से अपराध के बारे में जानकारी हो या यहां तक कि संदेह हो कि अपराध किया गया है। धारा 190(1) (सी) के तहत मजिस्ट्रेट इस आधार पर अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार रखता है कि अंतिम रिपोर्ट और उसके सामने रखे गए पुलिस रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, उसके पास संदेह करने का कारण है कि अपराध किया गया है। इसलिए, ये परिस्थितियां पुलिस से आरोप-पत्र मांगने की मजिस्ट्रेट की शक्ति को भी स्पष्ट रूप से नकारात्मक कर देंगी, जब उन्होंने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हो। अध्याय १४ की पूरी योजना स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए कोई मामला है या नहीं, इस बारे में राय का गठन पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी का है और वह राय निर्धारित करती है कि रिपोर्ट क्या है, धारा 170 के तहत "आरोप-पत्र" होना चाहिए या धारा 169 के तहत "अंतिम रिपोर्ट" होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि मजिस्ट्रेट जैसा कि हमने पहले ही बताया है, पुलिस की राय को स्वीकार या उससे असहमत हो सकता है और यदि वह

असहमत है तो वह हमारे द्वारा बताए गए कार्यप्रणाली में से किसी एक को अपना सकता है। लेकिन, वह पुलिस का आरोप-पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश नहीं दे सकता, क्योंकि रिपोर्ट प्रस्तुत करना पुलिस द्वारा गठित राय पर निभर्र करता है, न कि मजिस्ट्रेट की राय पर। मजिस्ट्रेट पुलिस को जांच पर विशेष राय बनाने और ऐसी राय के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। यह वास्तव में पुलिस ने क्षेत्र में अतिक्रमण होगा और पुलिस को राय बनाने के लिए मजबूर करना होगा, ताकि मजिस्ट्रेट के फैसले अनुरूप धारा 169 के तहत या धारा 170 के तहत, प्रकृति के आधार पर रिपोर्ट भेजी जा सके। संहिता के तहत उक्त कार्य पुलिस पर छोड़ दिया गया है।

जैसा कि तथ्यात्मक स्थिति से पता चलता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश पुलिस रिपोर्ट पर विचार करते हुए दिया गया और विरोध याचिका से संबंधित नहीं था। ऐसा होने पर उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है और किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अपील खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी शालिनी चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।